



# भारत का राजपत्र

## The Gazette of India

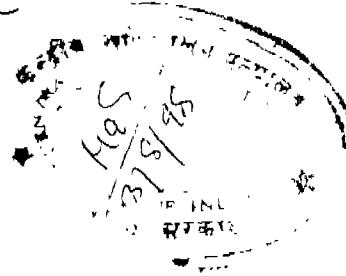
असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY



सं 20 ]

नई दिल्ली, बुधवार, अप्रैल 22, 1998/वैशाख 2, 1920

No. 20 ]

NEW DELHI, WEDNESDAY, APRIL 22, 1998/VAISAKHA 2, 1920

भारतीय पुनर्वास परिषद

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 अप्रैल, 1998

फा. सं. 5-62/93-आर.सी. आई.—भारतीय पुनर्वास परिषद, भारतीय पुनर्वास परिषद अधिनियम, 1992 (1992 का 34) की धारा 8 की उपधारा (3) और धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय सरकार को पूर्व मंजूरी से भारतीय पुनर्वास परिषद के सदस्य सचिव, अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की सेवा की शर्तें अवधारित करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाती है, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम, लागू होना और प्रारंभ (1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय पुनर्वास परिषद (सदस्य सचिव, अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की सेवा की शर्तें) विनियम, 1998 है ।
  - (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।
  - (3) ये ऐसे सदस्य सचिव, अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों को लागू होंगे, जो परिषद के पूर्णकालिक नियोजन में हैं ।
2. परिभाषा—इन विनियमों में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो :—
  - (क) “अधिनियम” से भारतीय पुनर्वास परिषद अधिनियम, 1992 (1992 का 34) अभिप्रेत है ;
  - (ख) “अध्यक्ष” से धारा 3 को उपधारा (3) के अधीन नियुक्त परिषद का अध्यक्ष अभिप्रेत है ;
  - (ग) “परिषद” से धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन गठित भारतीय पुनर्वास परिषद अभिप्रेत है ;
  - (घ) “कर्मचारी” से धारा 10 की उपधारा (1) के खंड (च) के उपबंधों और भर्ती विनियमों के उपबंधों के अनुसरण में परिषद द्वारा पूर्णकालिक नियोजन पर नियोजित कोई व्यक्ति अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत ऐसा कोई व्यक्ति भी है, जिसकी सेवाएं परिषद में प्रतिनियुक्त पर रखी गई हैं या जिसकी सेवाएं परिषद द्वारा किसी अन्य प्राधिकरण या संगठन के नियंत्रणाधीन रखी गई हैं ;
  - (ङ) “सदस्य-सचिव” से धारा 8 की उपधारा (1) के अधीन नियुक्त सदस्य सचिव अभिप्रेत है ;
  - (च) “अधिकारी” से ऐसा कोई व्यक्ति अभिप्रेत है जो भर्ती विनियम के उपबंधों के अनुसार परिषद द्वारा उस रूप में पूर्णकालिक नियोजन पर नियोजित है ;
  - (छ) “भर्ती विनियमों” से सदस्य-सचिव, अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की भर्ती की पद्धति को विनियमित करने के लिए बनाए गए नियम अभिप्रेत है ;

(ज) "धारा" से अधिनियम की धारा अभिप्रेत है ।

3. नियुक्ति (1) परिषद द्वारा सदस्य-सचिव, अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति, अधिनियम के उपबंधों के अधीन भर्ती की पद्धति को विनियमित करने के लिए बनाए गए भर्ती नियमों के उपबंधों और केंद्रीय सरकार के कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय (कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग) द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों और दिशा-निर्देशों के अनुसार की जाएंगी ।

(2) सदस्य-सचिव, अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों के पदों की संख्या, उनकी अर्हताएं, वेतनमान, भर्ती की पद्धति, परिवीक्षा की अवधि और अन्य शैक्षिक अर्हताएं वह होंगी जो भर्ती नियमों में विनिर्दिष्ट की जाएं ।

(3) पूर्णकालिक नियोजन पर नियोजित किए जाने वाला कोई व्यक्ति के बल तभी नियुक्त किया जाएगा जब वह कार्यग्रहण के समय निम्नलिखित प्रस्तुत करता है —

(क) मुख्य चिकित्सा अधिकारी या जिला अधिकारी या अन्य किसी प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी का चिकित्सा और आरोग्य प्रमाणपत्र;

(ख) शैक्षिक अर्हताओं, जन्म तिथि और अनुभव के समर्थन में मूल डिग्री या डिप्लोमा या प्रमाणपत्र;

(ग) सब-डिलीजनल मजिस्ट्रेट या किसी राजपत्रित अधिकारी या अन्य समतुल्य सक्षम प्राधिकारी का चरित्र, सत्यनिष्ठा और पूर्ववत प्रमाणपत्र;

(घ) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़े वर्ग या भूतपूर्व सैनिक या निःशक्तता, यदि लागू हो, का प्रमाणपत्र;

(ङ) यदि विवाहित है तो इस आशय का प्रमाणपत्र कि उसका या उसकी एक से अधिक जीवित, पत्नी या पति नहीं है :

परन्तु यदि परिषद का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह, ऐसे व्यक्ति और विवाह के दूसरे पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार विद्यमान हैं, तो वह ऐसे प्रमाणपत्र को प्रस्तुत करने से उस व्यक्ति को छूट दे सकती है ।

4. नियुक्ति प्राधिकारी—(1) ऐसे पदों के संबंध में, जिनका अधिकतम वेतनमान 13,500 रु. या अधिक है, सभी नियुक्तियां अध्यक्ष द्वारा केंद्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से की जाएंगी ।

(2) अन्य पदों के संबंध में नियुक्तियां सदस्य-सचिव द्वारा की जाएंगी ।

(3) परिषद का सदस्य-सचिव, अधिकारी और अन्य कर्मचारी, अध्यक्ष के साधारण अधीक्षण के अधीन अपने कृत्यों का निर्वहन करेंगे ।

5. वेतन और भत्ते—सदस्य-सचिव, अधिकारी और कर्मचारी भर्ती नियमों में विहित किए गए अनुसार, उनके द्वारा धारित पद के वेतनमान में वेतन के हकदार होंगे । वे समय-समय पर केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों को लागू दरों पर उनके वेतन के समनुचित महंगाई भत्ते और नगर प्रतिकरात्मक भत्ते के हकदार होंगे ।

6. छुट्टी की मंजूरी—(1) सदस्य-सचिव, अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की छुट्टी केंद्रीय सिविल सेवा (छुट्टी) नियम, 1972 और समय-समय पर केंद्रीय सरकार द्वारा तद्धीन जारी किए गए आदेशों के अनुसार शासित होंगी ।

(2) अध्यक्ष, सदस्य-सचिव के संबंध में छुट्टी मंजूर करने के लिए सक्षम प्राधिकारी होगा । अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों के संबंध में छुट्टी मंजूर करने के लिए सदस्य-सचिव सक्षम प्राधिकारी होगा ।

7. ज्येष्ठता—अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की ज्येष्ठता समय-समय पर केंद्रीय सरकार के कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय (कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग) द्वारा जारी किए गए आदेशों और अनुदेशों के अनुसार शासित होंगी ।

8. अधिवर्धिता की आयु—सदस्य-सचिव, अधिकारियों और समूह "घ" कर्मचारियों को छोड़कर अन्य कर्मचारियों की अधिवर्धिता की आयु 58 वर्ष होगी । समूह "घ" कर्मचारियों की अधिवर्धिता की आयु 60 वर्ष होगी ।

9. आचरण—(1) सदस्य-सचिव, प्रत्येक अधिकारी और प्रत्येक कर्मचारी सभी समयों पर पूर्ण सत्यनिष्ठा और कर्तव्य के प्रति निष्ठा बनाए रखेगा और ऐसा कुछ नहीं करेगा जो किसी अधिकारी या किसी कर्मचारी के लिए अशोभनीय है । सदस्य-सचिव, अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों का आचरण और व्यवहार केंद्रीय सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1964 और समय-समय पर केंद्रीय सरकार द्वारा तद्धीन जारी किए गए आदेशों के उपबंधों द्वारा शासित होगा ।

(2) सदस्य-सचिव, अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों के पदों का वर्गीकरण और अनुशासन, शासित का अधिरोपण, जांच अन्य संबंधित बातों के संबंध में अपील से संबंधित विषय, केंद्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियम, 1965 के उपबंधों के अनुसार शासित होंगे ।

(3) शासित अधिरोपित करने के लिए सक्षम प्राधिकारी निम्नलिखित होगा—

- (क) सदस्य-सचिव और समूह “क” अधिकारियों की दशा में, अध्यक्ष;
- (ख) अन्य कर्मचारियों की दशा में सदस्य सचिव ।

(4) कोई शासित अधिरोपित करने वाले अध्यक्ष के आदेश के विरुद्ध कोई अपील, केंद्रीय सरकार को होगी और सदस्य सचिव के आदेश के विरुद्ध अपील अध्यक्ष को होगी ।

10. चिकित्सीय उपचार के लिए सुविधाएं—

सदस्य-सचिव, अधिकारी और अन्य कर्मचारी (केंद्रीय सेवा) चिकित्सा परिचर्या नियम, 1944 के उपबंधों के अधीन उपबंधित किए गए अनुसार उनके बेतन के समुचित चिकित्सा उपचार और अस्पताल सुविधाओं के हकदार होंगे ।

11. छुट्टी यात्रा रियायत-सदस्य सचिव, अधिकारी और अन्य कर्मचारी उनके बेतन के समुचित छुट्टी यात्रा रियायत के लिए उसी दर पर, उन्हीं मानों और उन्हीं शर्तों पर हकदार होंगे जो समय-समय पर केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों को अनुज्ञेय हैं ।

12. यात्रा-भत्ता—(1) सदस्य-सचिव, अधिकारी और अन्य कर्मचारी परिषद की सेवा में की गई यात्राओं के लिए उनके बेतन के समुचित यात्रा-भत्ते, दैनिक भत्ते, अपने व्यक्तिगत समानों के परिवहन के लिए भत्ते और अन्य समान बातों के लिए उसी मान पर उन्हीं दरों पर और उन्हीं शर्तों पर हकदार होंगे जो समय-समय पर केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों को अनुज्ञेय हैं ।

(2) अध्यक्ष यात्रा भत्ता और अन्य भत्ते को मंजूर करने के लिए सक्षम प्राधिकारी होगा ।

13. बीपा—सदस्य-सचिव, प्रत्येक अधिकारी और प्रत्येक कर्मचारी उनके बेतन के समतुल्य जीवन बीमा सुरक्षा के लिए उसी रीति में, उन्हीं मानों पर और उन्हीं शर्तों पर हकदार होगा जैसे भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग) द्वारा फा.सं. 7 (5) ईवी/89 तारीख 1 नवम्बर, 1980 के अधीन अधिसूचित केंद्रीय सरकार कर्मचारी सामूहिक बीमा स्कीम, 1980 के अधीन केंद्रीय सरकार के कर्मचारी हकदार हैं ।

14. संपूर्ण भारत में सेवा करने का दायित्व—भर्ती विनियमों और इन विनियमों के उपबंधों के अधीन किसी अधिकारी या अन्य कर्मचारी के रूप में नियोजित कोई व्यक्ति भारत में कहाँ भी सेवा करने के दायित्वाधीन होगा ।

15. प्रशिक्षण लेने का दायित्व—इन विनियमों के उपबंधों के अधीन नियुक्त कोई व्यक्ति ऐसा प्रशिक्षण लेने के लिए दायी होगा और भारत में प्रशिक्षण के ऐसे पाठ्यक्रमों को भेजा जाएगा, जैसा सरकार समय-समय पर विनिश्चित करे । ऐसे किसी प्रशिक्षण या पाठ्यक्रम में, जिसकी अवधि छह मास या अधिक है या भारत के बाहर या भारत में प्राइवेट फर्मों या कारखानों में प्रशिक्षण के लिए भेजा गया कोई व्यक्ति, प्रशिक्षण की अवधि पर ध्यान दिए बिना प्रशिक्षण के पूरे व्यय या खर्च के प्रतिदाय के लिए दायी होगा, यदि किसी कारण से प्रशिक्षण के दौरान या ऐसे प्रशिक्षण के पूरा होने के पश्चात् तीन वर्ष की अवधि के भीतर वह अपनी सेवा में बने न रहने का विकल्प देता है ।

16. तथ्यों और जानकारी का छिपाया जाना—सदस्य-सचिव या किसी अधिकारी या किसी कर्मचारी द्वारा की गई किसी घोषणा या दी गई किसी जानकारी के मिथ्या या गलत पाए जाने या उसमें किसी तात्पर्यक जानकारी को जानबूझ कर छिपाया गया, पाए जाने की दशा में, वह परिषद के नियोजन से हटाए जाने के लिए दायी होगा/होगी और ऐसी किसी अन्य कार्रवाई के लिए भी दायी होगा/होगी, जो परिषद उसके विरुद्ध करना आवश्यक या उचित समझे ।

17. नियोजन में आवृत्ति—परिषद, सदस्य-सचिव किसी अधिकारी या किसी कर्मचारी के रूप में व्यक्तियों का नियोजन करते समय अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों, अन्य पिछड़े वर्गों और अन्य विशेष प्रवर्गों के व्यक्तियों के संबंध में उपबंधित किए जाने के लिए अपेक्षित पदों के आक्षण, आयु-सीमा की छूट और अन्य रियायतों की बाबत समय-समय पर केंद्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए आदेशों और अनुदेशों का पालन करेगा ।

18. सेवा की साधारण शर्तें—सदस्य-सचिव, अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की सेवा की साधारण शर्तें, जिसके अन्तर्गत बेतन, भत्ते मानदेय, प्रतिक्रियात्मक भत्ता, कार्यग्रहण समय, धारणाधिकार, पुष्टि, पदच्युति, हटाया जाना, निलंबन, सेवानिष्ठता और अन्य संबंधित विषय भी हैं, मूल नियमों और अनुपूरक नियमों, वित्तीय नियमों, केंद्रीय सेवा (अस्थायी सेवा) नियम, 1965 और केंद्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के उपबंधों के अनुसार शासित होंगी ।

19. सेवा के अभिलेख—परिषद, अनुपूरक नियमों के उपबंधों के अनुसार, सदस्य-सचिव, अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की सेवा-पुस्तका, गोपनीय रिपोर्ट और सेवा के अन्य अभिलेख रखेगी ।

## REHABILITATION COUNCIL OF INDIA

## NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd April, 1998

**File No. 5-62/93-RCI.**—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 8 and section 29 of the Rehabilitation Council of India Act, 1992 (34 of 1992) the Rehabilitation Council of India with the previous sanction of the Central Government hereby makes the following regulations for determining the conditions of service of Member-Secretary, the officers and other employees of the Rehabilitation Council of India, Namely :—

1. Short title, application and commencement.—(1) These regulations may be called the Rehabilitation Council of India (Conditions of Service of the Member-Secretary, officers and other employees) Regulations, 1998.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

(3) They shall apply to the Member-Secretary, such officers and other employees who are persons in whole time employment of the Council.

2. Definitions.—In these regulations, unless the context otherwise requires,—

(a) "Act" means the Rehabilitation Council of India Act, 1992 (34 of 1992);

(b) "Chairperson" means the Chairperson of the Council appointed under sub-section (3) of section 3;

(c) "Council" means the Rehabilitation Council of India constituted under sub-section (1) of section 3;

(d) "employee" means any person employed on whole time employment by the Council in accordance with the provisions of clause (f) of sub-section (1) of section 10 and the provisions of the recruitment regulations and shall include a person whose services are placed on deputation with the Council or whose services are placed by the Council at the disposal of any other authority or organisation;

(e) "Member-Secretary" means the Member-Secretary appointed under sub-section (1) of section 8;

(f) "officer" means any person employed as such on whole time employment by the Council in accordance with the provisions of the recruitment regulations;

(g) "recruitment regulation" means the regulations framed for regulating the method of recruitment of the Member-Secretary, officers and other employees;

(h) "section" means section of the Act.

3. Appointment.—(1) Appointment of the Member-Secretary, officers and other employees shall be made by the Council in accordance with the provisions of the recruitment regulations framed for regulating the method of recruitment under the provisions of the Act and in accordance with the instructions and guidelines issued by the Central Government in the Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions (Department of Personnel and Training) from time to time.

(2) The number of posts of the Member-Secretary, officers and other employees, their qualifications, scale of pay, method of recruitment, age limit, period of probation and other educational qualifications shall be such as may be specified in the recruitment regulations.

(3) Any person to be employed on whole time employment shall be appointed only when he produces at the time of joining,—

(a) Medical and fitness certificate from the Chief Medical Officer or District Medical Officer or any other Authorised Medical Officer;

(b) Original Degree or Diploma or Certificate in support of the educational qualifications, date of birth and experience;

(c) Character, integrity and antecedents certificate from the Sub-Divisional Magistrate or any gazetted officer or other equivalent competent authority;

(d) Certificate of the Scheduled Caste or the Scheduled Tribe or other backward classes or ex-serviceman or disability, if applicable.

(e) if married, certificate to the effect that he/she is not having more than one living wife/husband.

Provided that the Council may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, except any person from the production of such certificate

4. Appointing authority—(1) All appointments to the posts maximum of the pay scale of which is rupees Thirteen Thousand and Five Hundred or above shall be made by the Chairperson with the previous approval of the Central Government.

(2) Appointments to the other posts shall be made by the Member-Secretary.

(3) The Member-Secretary, officers and other employees of the Council shall discharge their functions under the general superintendence or the Chairperson.

5. Salaries and allowances—The Member-Secretary, Officers and other employees shall be entitled to salary in the scale of the post held by them as specified in the recruitment regulations. They shall be entitled to dearness allowance and city compensatory allowance appropriate to their pay at the rates admissible to the Central Government employees from time to time.

6. Grant of leave—(1) The leave of the Member-Secretary, Officers and other employees shall be governed in accordance with the provisions of the Central Civil Service (Leave) Rules, 1972 and orders issued thereunder by the Central Government from time to time.

(2) The Chairperson shall be the authority competent to sanction leave in respect of the Member-Secretary. The Member-Secretary shall be the authority competent to sanction leave in respect of the officers and other employees.

7. Seniority—Seniority of the officers and other employees shall be governed in accordance with the orders and instructions by the Central Government in the Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions (Department of Personnel and training) from time to time.

8. Superannuation—The age of superannuation for the Member-Secretary, officers and other employees, except Group 'D' employees, shall be 58 years. The age of superannuation for Group 'D' employees shall be 60 years.

9. Conduct.—(1) The Member-Secretary, every officer and every employee shall at all times maintain absolute integrity, devotion to duty and do nothing which is unbecoming of an officer or an employee. The conduct and behaviour of the Member-Secretary, officers and other employees shall be governed by the provisions of the Central Civil Services (Conduct) Rules, 1964 and the orders issued thereunder by the Central Government from time to time.

(2) The classification of the posts of the Member-Secretary, officers and other employees and the matters relating to discipline, imposition of penalty, inquiry, appeal of other related things shall be governed in accordance with the provisions of the Central Civil Services (Classification, Control and Appeal) Rules, 1965.

(3) The authority competent to impose a penalty shall be—

- (a) in the case of Member-Secretary and Group 'A' Officers, the Chairperson;
- (b) in the case of other employees, the Member-Secretary.

(4) An appeal against the order of the Chairperson imposing a penalty shall lie to the Central Government and against the order of the Member-Secretary to the Chairperson.

10. Facilities for medical treatment.—The Member-Secretary, officers and other employees shall be entitled to medical treatment and hospital facilities appropriate to their pay as provided under the provisions of the (Central Service) Medical Attendance Rules, 1944.

11. Leave travel concession.—The Member-Secretary, officers and other employees shall be entitled to leave travel concession appropriate to their pay at the same rate, at the same scales and on the same conditions as are admissible to the Central Government employees from time to time.

12. Travelling Allowance.—(1) The Member-Secretary, officers and other employees shall be entitled to the travelling allowance for journeys performed in the service of the Council, daily allowance, allowance for transportation of personal effects and other similar matters appropriate to their pay at the same scale, at the same rates and on the same conditions as are admissible to the Central Government employees from time to time.

(2) The Chairperson shall be authority competent to sanction the travelling allowance and other allowances.

13. Insurance.—The Member-Secretary, every officer and every employee shall be entitled to life insurance cover appropriate to their pay in the same manner, at the same scales and on the same conditions as the Central Government employees are entitled under the Central Government Employees Group Insurance Scheme, 1980 notified by the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Expenditure) Vide No. F. 7(5)-EV/89, dated the 1st November, 1980.

14. Liability to serve throughout India.—Any person employed as an officer or other employee under the provisions of the recruitment regulations and these regulations shall be liable to serve anywhere in India.

15. Liability to undergo training.—Any person appointed under the provisions of these regulations shall be liable to undergo such training and be detailed on courses of instruction in India as the Government may decide from time to time. Any person detailed for training or course, the duration of which is six months or more or any person detailed for training outside India or with private firms or factories in India, irrespective of the duration of the training, shall be liable to refund in full the expenses or cost of training, if, for any reason, during the training or within a period of three years after the completion of such training, he opts to discontinue his service.

16. Suppression of facts and information.—If any declaration given or information furnished by the Member-Secretary or an officer or an employee proves to be false or incorrect or found to have wilfully suppressed any material information, he/she shall be liable to be removed from the employment of the Council and shall also be liable for such other action as the Council may deem necessary or proper to be taken against him/her.

17. Reservation in employment.—The Council, while making the employment of persons as a Member-Secretary, an officer or an employee, shall adhere to the orders and instructions issued by the Central Government from time to time regarding reservation of posts, relaxation of age limit and other concessions required to be provided to the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Ex-Servicemen, other backward Classes and other special categories of persons.

18. General conditions of service.—The general conditions of the service of the Member-Secretary, officers and other employees including pay, allowances, honorarium, compensatory allowance, joining time, lien, confirmation, dismissal, removal, suspension, retirement and other related matters shall be governed in accordance with the provisions of the Fundamental Rules and Supplementary Rules, Financial rules, Central Service (Temporary Service) Rules, 1965 and orders issued by the Central Government from time to time.

19. Records of service.—The Council shall maintain the service book, confidential reports and other service records of the Member-Secretary, officers and other employees in accordance with the provisions of Supplementary Rules.

DR. B. P. YADAV, Chairman

भारतीय पुनर्वास परिषद

आधिकारिक

नई दिल्ली, 22 अप्रैल, 1998

फा.सं. 5-62/93-आर.सी. आई.—भारतीय पुनर्वास परिषद अधिनियम, 1992 (1992 का 34) की धारा 21 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय सरकार की पूर्व मंजूरी से निम्नलिखित विनियम बनाती है, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ—(1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय पुनर्वास परिषद (पुनर्वास वृतिकों के लिए वृतिक आचरण के मानक, शिष्टाचार और नैतिक संहिता) विनियम, 1998 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगे।

2. परिभाषाएं—इन विनियमों में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो :—

(क) "अधिनियम" से भारतीय पुनर्वास परिषद अधिनियम, 1992 (1992 का 34) अभिप्रेत है,

(ख) "परिषद" से अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन गठित परिषद अभिप्रेत है,

(ग) "प्ररूप" से विनियमों से संलग्न प्ररूप अभिप्रेत है,

(घ) "प्रेक्टिस" से किसी पुनर्वास वृतिक द्वारा निश्चक्तता ग्रस्त व्यक्ति का किया गया उपचार अभिप्रेत है जिसके अन्तर्गत परामर्श देना, शिक्षण और सहायकों तथा साधित्रों की फॉटिंग या उनका समायोजन भी है,

(ङ) "वृतिक" से धारा 2 की उपधारा (1) के खंड (ङ) के अधीन परिभाषित पुनर्वास वृतिक अभिप्रेत है,

(च) "धारा" से अधिनियम की धारा अभिप्रेत है,

(छ) सभी अन्य शब्दों और पदों का, जो इन विनियमों में प्रयुक्त किए गए हैं और परिभाषित नहीं किए गए हैं, केन्द्र अधिनियम में परिभाषित किए गए हैं, के वही अर्थ होंगे जो अधिनियम में क्रमशः उनके लिए समनुदेशित किए गए हैं।

3. विज्ञापन और प्रचार का प्रतिशेष—कोई वृतिक किसी निःशक्तात्प्रस्त व्यक्ति को, प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से, या तो स्वयं या किसी समाचार पत्र, पत्रिका या पुस्तिका में किसी प्रकार के प्रचार या विज्ञापन के माध्यम से या किसी डाक्युमेन्टरी फिल्म या एलेकार्ड के माध्यम से या किसी परिपत्र, कार्ड, हुंडी, फोटो या चार्ट द्वारा, प्रलोभन नहीं देगा।

परन्तु वृतिक किसी प्रेस मीडिया के माध्यम से या किसी अन्य माध्यम द्वारा अपनी प्रेक्टिस आरंभ करने या पुनः आरंभ करने, प्रेक्टिस की प्रकृति के परिवर्तन, प्रेक्टिस के स्थान या निवास के पते के परिवर्तन, प्रेक्टिस के स्थान से अस्थायी अनुपस्थिति, व्यवसाय के परिसमापन या किसी अन्य व्यवसाय में चले जाने के बारे में औपचारिक उद्घोषणा जारी कर सकेगा।

परन्तु यह और कि वृतिक कौशल या विज्ञान के संबंधन के लिए लिखित या प्रकाशित पूर्व रूप से अनुसंधान, चिकित्सा या विज्ञान साहित्य को लिख या प्रकाशित कर सकेगा।

4. वृतिक द्वारा घोषणा—प्रत्येक वृतिक, धारा 19 के अधीन रजिस्ट्रेशन के समय इन विनियमों से उपबद्ध प्ररूप में एक प्रतिज्ञान या घोषणा करेगा और उसे हस्ताक्षरित करेगा तथा उनके पालन करने का करार करेगा।

5. रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र में संशोधन—(1) कोई भी वृत्तिक या तो स्वयं या किसी अन्य व्यक्ति के माध्यम से परिषद द्वारा जारी किए गए रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र की विशिष्टियों में कोई संशोधन, परिवर्तन या विदूषण नहीं करेगा। यदि रजिस्ट्रेशन के समय घोषित किए गए वृत्तिक के पते, अर्हताओं या किहीं अन्य विशिष्टियों में कोई परिवर्तन अपेक्षित है तो ऐसे परिवर्तन की तारीख से 30 दिन की अवधि के भीतर वृत्तिक द्वारा परिषद को ऐसे परिवर्तन की सूचना दी जाएगी और रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र तदनुसार सदस्य सचिव से संशोधित कराया जाएगा। रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र में पते या किन्हीं अन्य विशिष्टियों के संशोधन या परिवर्तन सदस्य-सचिव के द्वारा सम्यक रूप से अधिप्रमाणित किए जाएंगे।

(2) वृत्तिक रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र को संशोधित कराने की दृष्टि से मूल रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र को या तो स्वयं या अपने प्राधिकृत अधिकारी के माध्यम से प्रस्तुत करेगा या रजिस्ट्रीकृत डाक के अधीन उसे भद्रस्य सचिव को भेजेगा।

(3) सदस्य-सचिव रजिस्टर और रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र में आवश्यक और अपेक्षित संशोधन करेगा। रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र में किए गए संशोधन मदस्य-सचिव द्वारा सम्यक रूप से अधिप्रमाणित किए जाएंगे।

6. वृत्तिक के नाम या उपनाम में परिवर्तन—(1) यदि नाम या उपनाम में जो रजिस्ट्रेशन के समय घोषित किया गया है, कोई परिवर्तन अपेक्षित है तो वृत्तिक द्वारा परिषद को ऐसे परिवर्तन की सूचना दी जाएगी। ऐसी सूचना के साथ निम्नलिखित होगा।

(क) नाम या उपनाम के ऐसे परिवर्तन, लोप या, परिवर्धन के संबंध में राजपत्र में या किसी राष्ट्रीय दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित अधिसूचना की एक प्रति, या

(ख) नाम या उपनाम के ऐसे परिवर्तन, लोप या परिवर्धन के संबंध में न्यायिक मजिस्ट्रेट या मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रतिज्ञान और अधिप्रमाणित किया गया एक शापथपत्र,

(ग) मूल रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र।

(2) सदस्य-सचिव रजिस्टर और रजिस्ट्रीकरण में आवश्यक और अपेक्षित संशोधन या परिवर्तन करेगा। रजिस्ट्रेशन प्रमाणपत्र में किए गए संशोधन या परिवर्तन सदस्य सचिव द्वारा सम्यक रूप से अधिप्रमाणित किए जाएंगे।

7. प्रेक्टिस और निवास के स्थान का परिवर्तन—यदि प्रेक्टिस या निवास के स्थान में जो रजिस्ट्रेशन के समय घोषित किया गया है, में कोई परिवर्तन होता है तो ऐसे परिवर्तन की तारीख से तीस दिन के भीतर वृत्तिक ऐसे परिवर्तनों की सूचना परिषद को देगा और विनियम 5 के उपनियन्यम (2) के अधीन उपबंधित प्रक्रिया के अनुसार अपने रजिस्ट्रोकरण प्रमाणपत्र को संशोधित कराएगा।

8. अर्हताओं और रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र का दिखाया जाना—(1) प्रत्येक वृत्तिक अपनी सही डिग्री या डिप्लोमा, साइनबोर्ड, पत्रशीर्ष, पैड, नृसंखा पर्ची, विजिटिंग कार्ड, प्रमाणपत्र, रिपोर्ट और उसके हस्ताक्षर से जारी किए जाने वाले अन्य दस्तावेजों पर दर्शाएगा।

(2) रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र की एक प्रति उस परिसर के ऐसे सहजदृश्य स्थान पर व्यक्तिकाई जाएगी जहां वह वृत्तिक प्रेक्टिस करता है।

9. वृत्तिक सेवा के लिए संदाय—कोई वृत्तिक “आराम नहीं, फीस नहीं” जैसी संविदा नहीं करेगा। परामर्श फीस, औषधियों या अन्य सहायताओं और माधित्रों की बाबत या इसी प्रकार की अन्य सेवा के लिए लिए जाने वाले प्रभार अत्याधिक नहीं होंगे।

10. पुर्वानुमान का प्रतिशेष—कोई भी वृत्तिक स्वयं को किसी निःशक्तताग्रस्त व्यक्ति की रोग के अनुक्रम में पुर्वानुमान करने में या उसकी गम्भीर दशा को बढ़ा-चढ़ाकर बताने में लिप्त नहीं रहेगा।

11. कृतिस्त आचरण—यदि कोई वृत्तिक,—

(क) रोग के अनुक्रम का पुर्वानुमान को बढ़ा बढ़ा कर बताने में लिप्त होता है,

(ख) किसी अनर्यादित कार्य में सम्मिलित होता है,

(ग) किसी निःशक्तता ग्रस्त व्यक्ति के साथ अनुचित या अनैतिक संबंध बनाए रखता है,

(घ) किसी निःशक्तता ग्रस्त व्यक्ति के साथ कठोर और रुक्षी भाषा का प्रयोग करता है,

(ङ) अत्याधिक परामर्श फीस या सेवा प्रभार लेता है,

(च) किसी निःशक्तता ग्रस्त व्यक्ति की मानसिक या शारीरिक व्याधि से अनपेक्षित लाभ लेता है,

(ङ) किसी निःशक्तता ग्रस्त व्यक्ति को जानबूझकर कोई निम्न स्तर के सहायक या साधित्र, अंतःस्थापित करता है, लगाता है या समायोजित करता है,

(ज) नियमित और अपेक्षित अंतरालों पर या उचित समय पर निःशक्तता ग्रस्त व्यक्ति का पुनर्वास या उपचार नहीं करता है,

(झ) जानबूझकर या आशित रूप से किसी निःशक्तता ग्रस्त व्यक्ति की उपेक्षा करता है,

(ज) निःशक्तता ग्रस्त व्यक्तियों के लिए दिए गए किसी फायदे का उपभोग करता है या उपभोग करने का प्रयास करता है, या

(ट) अपनी विशेषज्ञता से भिन्न किसी क्षेत्र में प्रेक्टिस करता है; तो उसे कृतिस्त आचरण वाले वृत्तिक के रूप में घोषित किया जाएगा।

12. जानकारी का प्रस्तुत किया जाना—जब कभी वृत्तिक की अर्हताओं, प्रेक्टिस के स्थान या निवास की बाबत कोई जानकारी या किसी अन्य प्रभार की जानकारी परिषद या केन्द्रीय सरकार द्वारा अपेक्षित की जाती है, तो वृत्तिक उसे बिना किसी विलम्ब के प्रस्तुत करेगा।

13. रजिस्टर आदि का रखा जाना - प्रत्येक वृत्तिक परीक्षण किए गए व्यक्तियों, प्रमाणपत्रों, रिपोर्टों या जारी किए गए नुस्खों का उचित दैनिक अभिलेख और उसके द्वारा प्राप्त की गई परामर्श फीस, सेवा प्रभार और अन्य प्रभारों का लेखा-जोखा रखेगा।

14. दस्तावेजों आदि का प्रस्तुत किया जाना - जब कभी मान्यताप्राप्त अर्हताएं, रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र की विधिमान्यता निश्चित करने की दृष्टि से या किसी अन्य विषय के संबंध में सदस्य-सचिव द्वारा या केन्द्रीय सरकार या सदस्य सचिव द्वारा इस निमित्स सम्यक रूप से प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी द्वारा दस्तावेजों की, जिसके अन्तर्गत किसी वृत्तिक के कब्जे में या उसके नियंत्रनाधीन कोई रजिस्टर, प्रमाणपत्र, लेखा-बहियां या अन्य कागजपत्र भी हैं, जांच या निरीक्षण किया जाना अपेक्षित है, वहां वृत्तिक उन्हें जांच या निरीक्षण किया जाना अपेक्षित है, वहां वृत्तिक उन्हें जांच या निरीक्षण के लिए सदस्य-सचिव या प्राधिकृत अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करेगा।

15. विनियमों के उल्लंघन के परिणाम - यदि ऐसी जांच के पश्चात, जो परिषद न्यायसंगत और उचित समझे, कोई वृत्तिक इन विनियमों के सभी या किसी उपबंधों के उल्लंघन का दोषी पाया जाता है, तो वह कुत्सित आचरण वाले वृत्तिक के रूप में घोषित किए जाने के लिए दायी होगा या उसके नाम की धारा 21 की उपधारा (3) के उपबंधों के अनुसार रजिस्टर से हटाये जाने का आदेश किया जा सकेगा।

### प्रस्तुत

( विनियम 4 देखिए )

### घोषणा का प्रस्तुत

मैं, ..... सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ कि मैं भारत के लोगों और मानवता की सेवा और भलाई के लिए स्वयं को समर्पित करूँगा मैं अपने सर्वोत्तम सार्वज्ञ और ज्ञान से उस वृत्ति, जिसमें मैं पदार्पण करने वाला हूँ, के कर्तव्यों का निर्वहन ईमानदारी से और तत्परतापूर्वक, निष्ठापूर्वक और किसी भय, पक्षपात या दुर्भावना के बिना करूँगा, कि मैं वृत्ति की मर्यादा, सम्मान और उत्कृष्ट परंपरा को बनाए रखूँगा, कि निश्चक्तता ग्रस्त व्यक्तियों का पुनर्वास मेरा सर्वोत्तम प्रयास होगा और मैं वृत्तिक आचारण की गोपनियता और मानकों तथा शिष्टाचार बनाए रखूँगा और उनका सम्मान करूँगा और भारतीय पुनर्वास परिषद (पुनर्वास वृत्तिकों के लिए वृत्तिक आचरण के मानक, शिष्टाचार और नैतिक संहिता) विनियम, 1998 में अधिकथित नैतिक संहिता का पालन करूँगा।

मैं ..... आज तारीख ..... 1998/99 को बिना किसी आहरी दबाव के यह घोषणा करता हूँ और उनके पालन करने के लिए सहमति देता हूँ।

परिषद की मुद्रा

वृत्तिक के हस्ताक्षर

सदस्य सचिव के हस्ताक्षर

डा. बी. पी. यादव, अध्यक्ष

## REHABILITATION COUNCIL OF INDIA

### NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd April, 1998

F. No. 5-62/93-RCI.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 21 and Section 29 of the Rehabilitation Council of India Act, 1992 (34 of 1992) the Rehabilitation Council of India with the previous sanction of the Central Government hereby makes the following regulations namely :—

1. Short title and commencement.—(1) These regulations may be called the Rehabilitation Council of India (Standards of Professional Conduct, Etiquette and Code of Ethics for Rehabilitation Professionals) Regulations, 1998.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. Definitions.—In these regulations, unless the context otherwise requires,—
  - (a) “Act” means the Rehabilitation Council of India Act, 1992 (34 of 1992);
  - (b) “Council” means the Rehabilitation Council of India constituted under sub-section (1) of Section 3 of the Act ;
  - (c) “form” means the form annexed to these regulations;
  - (d) “practice” means the treatment of persons with disabilities undertaken by a rehabilitation professional and include the Counselling, teaching and fitting or adjustment of aids and appliances;
  - (e) “professional” means a rehabilitation professional defined under clause (n) of sub-section (1) of Section 2;
  - (f) “section” means section of the Act ;
  - (g) all other words and expressions used in these regulations and not defined but defined in the Act, shall have the meanings respectively assigned to them in the Act.

3. Prohibition of advertisement and publicity.—A professional shall not solicit any person with disabilities, directly or indirectly, either personally, or through any kinds of publicity or advertisement in any newspaper, magazine or pamphlet, or through any documentary film or placard, or by distribution of any circular, card, hand-bill, photograph or chart :

Provided that a professional may issue a formal announcement through any press media or by any other mode about starting or resumption of his practice, change of kinds of practice, change of address of the place of practice or residence, temporary absence from the place of practice, winding up the profession or switching over to another professions :

Provided further that a professional may write or publish a purely research, medical or science literature written or published for the advancement of the professional skill or science.

4. Declaration by professional.— At the time registration under section 19, every professional shall make and subscribe an affirmation or a declaration in the Form appended to these regulations and shall agree to abide by the same.

5. Amendment in registration certificate.—(1) No professional shall either himself or through some other person make any amendment, change or disfigurement of particulars of the registration certificate issued by the Council. If any change in the address, qualifications or any other particulars of the professional, as declared at the time of registration is required, a notice of such change shall be given by the professional to the Council within a period of thirty days from the date of such change and the registration certificate got amended from the Member-secretary accordingly. The amendments or change of address or any other particulars in the registration certificate shall be duly authenticated by the Member-Secretary.

(2) With a view to get the registration certificate amended the professional shall either produce the original registration certificate personally or through his authorised agent or send the same to the Member-Secretary under registered post

(3) The Member-Secretary shall make necessary and required amendments in the Register and the registration certificate. The amendments made in the registration certificate shall be duly authenticated by the Member-Secretary.

6. Change the name or surname of professional.—(1) If any change of the name or surname, as declared at the time of registration is required, a notice of such change shall be given by the professional to the Council. Such notice shall be accompanied by,--

(a) a copy of the notification published in the Official Gazette or in any national daily newspaper relating to such alteration, omission or addition of name or surname; or

(b) an affidavit regarding such alteration, omission or addition of name or surname affirmed and authenticated before a Judicial Magistrate or Metropolitan Magistrate; and

(c) the registration certificate in original.

(2) The Member-Secretary shall make necessary and required amendments or changes in the Register and the registration certificate. The amendments or changes made in the registration certificate shall be duly authenticated by the Member-Secretary.

7. Change of place of practice and residence.—If any change takes place in the place of practice or of residence as declared at the time of registration, the professional shall give a notice of such change to the Council within a period of thirty days from the date of change and get his registration certificate amended in accordance with the procedure provided under sub-regulation (2) of regulation 5.

8. Display of qualifications and registration certificate.—(1) Every professional shall display his correct Degree or Diploma on the sign board, letter head pad, prescription slip, visiting card, certificate, report and on other kind of documents to be issued under his signature.

(2) A copy of the registration certificate shall be affixed on a conspicuous place in the premises where the professional is practising.

9. Payment for professional service.—No professional shall enter into a contract of "No cure, No payment". The consultation fee, the charges in respect of medicaments or other aids and appliances or any other kind of service, shall not be exorbitant.

10. Prohibition of prognosis.—No professional shall indulge himself in exaggeration of forecasting of the course of disease or gravity of the condition of any person with disability.

11. Infamous conduct.—If a professional,—

(a) indulge in exaggeration of forecasting of course of disease;

(b) involve in any indecent act;

(c) maintain improper or illicit relations with any person with disability;

- (d) make use of harsh and rough language with any person with disability;
- (e) charge exorbitant consultation fee or service charges;
- (f) take any undue advantage from the mental or physical affliction of a person with disability;
- (g) insert, affix or adjust knowingly any non-standard aids or appliance to a person with disability;
- (h) does not undertake the rehabilitation or treatment of persons with disabilities on regular and required intervals or proper time;
- (i) neglects knowingly and intentionally any person with disability;
- (j) avails or attempt to avail any benefit meant for persons with disabilities; or
- (k) undertake practice in any field other than his specialisation,

shall be declared as professional of infamous conduct.

12. Submission of information.—Whenever any information in respect of the qualifications, practice, place of practice or residence of professional or any other kind of information is required by the Council or the Central Government, of professional shall submit the same without any delay.

13. Maintenance of register, etc.—Every professional shall maintain the proper daily records of persons examined, the certificates, reports or prescriptions issued and the accounts of consultation fee, service charges and other charges received by him.

14. Production of documents, etc.—Whenever the documents including any register, certificate, account books, or other papers in possession of or under the control of any professional are required to be examined or inspected with a view to ascertain the recognised qualifications, validity of the registration certificate or in connection with any other matter by the Member-Secretary or by any other officer duly authorised in this behalf by the Central Government or by the Member-Secretary, the professional shall produce the same for examination or inspection before the Member-Secretary or such authorised officer.

15. Consequences for contravention of regulations.—If, after such inquiry as the Council may deem just and proper, any professional is found guilty of contravention of all or any of the provisions of these regulations, shall be liable to be declared as professional having infamous conduct or his name may be ordered to be removed from the Register in accordance with the provisions of sub-section (3) of section 21.

**Form**

(See regulation 4)

**Form of declaration**

I, \_\_\_\_\_, do solemnly affirm that I shall devote myself to the service and well being of the people of India and humanity, that to the best of my ability and knowledge I shall honestly, diligently, faithfully and without any fear, favour or ill-will discharge the duties of the profession upon which I am about to enter, that I shall uphold and maintain the honour and noble tradition of the profession, that the rehabilitation of the persons with disabilities shall be my best consideration and I shall maintain and respect the secrets and standards of professional conduct and etiquette and observe the code of ethics laid down in the Rehabilitation Council of India (Standard of Professional Conduct, Etiquette and Code of Ethics for Rehabilitation Professionals) Regulations, 1998.

I, \_\_\_\_\_, make this declaration on this \_\_\_\_\_ day of, 1998/99 without any outside pressure and agree to abide by the same.

**Signature of the professional**

Seal of the Council

**Signature of the Member-Secretary**

**DR. B.P. YADAV, CHAIRMAN**